

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 189/2017

सन्दीप सहारण पुत्र मुखराम सहारण जाति जाट निवासी 13 क्यू बखताना
तहसील व श्रीगंगानगर।

— अपीलार्थी

बनाम

1. शिवप्रकाश
 2. वेदप्रकाश
 3. जयप्रकाश
 4. राजस्थान
- पिसरान हजारीराम जाति जाट निवासी 13 क्यू
बखताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
—रेस्पोडेन्टान



अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरुद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 18.12.2017

उपस्थिति:—

श्री राजेश गुम्बर अभिभाषक अपीलार्थी


श्री प्रदीप सिहाग अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक :- 26.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 251क के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की चक 11 क्यू बखताना के खाता संख्या 56/51 मु.नं. 33 के कि.न. 4 में 10 बिस्वा व कि.नं. 5 से 7 सालम भूमि है। प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतु मु.नं. 33 के कि.न. 14 में पूर्व हिस्सा में 2-2 बिस्वा यानि 16-1/2 गुणा 495 फुट चालू हालत में है, इसी रास्ता से मुख्य सड़क पर


26/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आया जा सकता है, अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। अतः निवेदन है कि उक्त रास्ता को स्वीकृत करने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थना पत्र का जबाव अप्रार्थीगण ने पेश कर कथन किया कि प्रार्थी राजकीय सेवा में है, प्रार्थी काशत नहीं करता है, उसने अपनी भूमि का पानी इसी चक के मु.नं. 29 के खातेदार को दिया हुआ है। रास्ता मौका पर चालू नहीं है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 18.12.2017 को प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रार्थी/अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार मु.नं. 33 के कि.नं. 15, 16, 25 में रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। उक्त भूमि रेस्पों. संख्या 3 जयप्रकाश के नाम से दर्ज है। अधी.न्यायालय को तहसीलदार की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर रास्ता स्वीकृत करना चाहिए था जो स्वीकृत नहीं करने में अधी.न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अतः निवेदन है कि मु.नं. 33 के कि.नं. 15, 16, 25 में रास्ता स्वीकृत किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी राजकीय सेवा में है एवं स्वयं काशत नहीं करता है। अधी.न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 08.12.2017 के विरुद्ध पेश की है, जिसमें अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए खारिज किया है जबकि



24/2/18
राजस्थान अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज)

खारिजी का आधार इन्तकाल की अपील लम्बित होकर सीसीपी की धारा 10 के तहत खारिज किया है तथा अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ते की निहायत ही आवश्यकता होने से अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त कर रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट संदीप सहारण को अपनी कृषि भूमि तहसीलदार श्रीगंगानगर के चक 11 क्यू.मु.नं. 33 में पहुंचने के लिए रास्ता की आवश्यकता होने पर रेस्पो. की खातेदारी भूमि में रास्ता स्वीकृत करने का आवेदन अन्तर्गत रा.का.अ. 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत पेश किया है जिसकी Bare reading है कि "251-A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.— (1) Where—(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings— and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that—

- (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and
- (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved— may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along the line demar-cated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way, not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right



26/2/18
राजस्व अपील प्राधिकरण
श्रीगंगानगर (राज.)

to lay pipeline or have a new way, or enlarge or widen an existing way is granted.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted."

इस धारा की क्रियान्वति हेतु राज्य सरकार का Notification क्रमांक N.F. 3(2) Rev 6/03/pt 7/जयपुर दिनांक 02.03.12 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 2012 में संशोधन कर नियम 68 ये 70 में रास्ता स्वीकृति का

Substantive and procedural law का समावेश विधि में किया गया है जिसकी

* Bare reading है कि 68. Application under section 251-A.- An application for grant of permission under sub-section (1) of 251-A of the Act shall be in Form I.

69. Enquiry and disposal of application.- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation.- (1) The amount of compensation payable under sub-section (1) of section 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:—

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.



26/2/18
राजस्थान हाईकोर्ट
श्रीमान न्यायाधीश (राज.)

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to -

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined."

परन्तु अधी.न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है उसका क्रियात्मक हिस्सा है कि तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इन्तकाल की अपील इस न्यायालय में विचाराधीन है। विवादित भूमि संयुक्त खाते की भूमि में जिसमें प्रार्थी का अलग खाता कायम नहीं करवाया गया है। जिस कारण रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रा.का.अ. 1955 की धारा 251(क) अस्वीकार किया जाता है। अधी.न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें रास्ते की आवश्यकता प्रतिपादित है परन्तु इस रिपोर्ट को Ignore किया है जो नियम 69 का स्पष्ट उल्लंघन है साथ ही रास्ता स्वीकृति का प्रार्थना पत्र क्रियात्मक आदेश में दर्शाए है वे धारा 251ए पठित नियम 69 के विपरीत है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2017 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/16/2820 दिनांक 07.11.2016 के प्रस्ताव अनुसार चक 11 क्यू बखताना के मु.नं. 33 के कि.नं. 15, 16, 25 में 1-1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।



26/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रास्ता में आने वाली भूमि की एवज में प्रार्थी/अपीलांत डी.एल.सी. की दुगनी राशि अदा करेगा एवं तहसीलदार नियम 70 की पालना कर रास्ते का रेकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया

गया।



(Handwritten signature and date)
26/2/18
(प्रेमराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर